(b) The National Telecom Policy 1994 envisages provision of Telephone connections practically on demand by 31-3-97.

(c) and (b) Yes, Sir. Basic services are being opened to private sector to augmen the efforts of DOT in meeting the National Telecom. Policy 1994 objectives.

Conversion of Telephone Exchange in Muzaffarnagar into Electronic Exchange

1945. SHRIMATI MALTI SHARMA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that telephone exchange in Muzaffarnagar (U.P.) is partially electronic ;

(b) whether it is also a fact that telephone users of the part of the telephone exchange which is not electronic are facing difficulties due to frequent breakdowns in telephone services ;

(c) if so, whether there is a proposal to convert the above telephone exchange into fully electronic ; and

(d) if so, when the above job is likely to be completed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) The subscribers of non-electronic exchange are not getting as efficient service as these of electronic exchange.

(c) Yes, Sir.

(d) The non-electronic exchange is planned to be converted into electronic exchange Progressively during 1994-95 and 1995-96.

Postal System Out of Gear in Jaipur

1946. SHRI GAYA SINGH :
SHRI N. GIRI PRASAD : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "Postal System out of gear in Jaipur" appearing in "The Hindu" dated the 29th November, 1994 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) what steps are proposed to be taken to appoint sufficient staff to make the postal delivery system efficient and prompt ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) The postal system in Jaipur city was put to strain due to heavy receipt of mail during the last Diwali period. Adequate steps were taken by the local postal authorities for the disposal of the additional work.

(c) The workload of postal delivery staff is reviewed periodically and appropriate remedial measures are taken.

उत्पीड़ित टेलीफोन उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाना

1947. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

श्री राम जेठमलानी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले महीनों के दौरान जिला उपभोक्ता न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कतिपय अधिकारियों द्वारा कतिपय टेलीफोन उपभोक्ताओं को उत्पीड़ित किया गया है, अतः क्षतिपूर्ति के रूप में निगम को उन्हें 5,000 रुपए देना होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम ने अब संबंधित व्यक्तियों को उक्त राशि का भुगतान कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में दोषी पाये गये निगम के अधिकारियों या कर्मचारियों के नाम क्या हैं तथा उनके दोष क्या-क्या थे और क्या सरकार ने उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है, यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों को क्या दंड दिया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जुलाई, 94 के बाद, पिछले कुछ महीनों में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में निम्नलिखित मामलों का निपटान किया गया है जिनमें 5000/-रु० का हर्जाना दिया गया है और इसे एम टी एन एल के संबंधित अधिकारियों से वसूल करने का निदेश दिया गया है :

	आदेश जारी करने की तारीख
सर्वश्री	
1. एन० के० तलवाड़ बनाम एम टी एन एल	8-7-94
2. नलिनी त्रिपाठी बनाम एम टी एन एल	8-7-94
3. आर० एम० वत्स बनाम एम टी एन एल	7-10-94

(ख) उपर्युक्त क्रम सं० 2 और 3 में उल्लिखित मामलों के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली में अपील लंबित है । क्रम सं० 1 पर उल्लिखित पार्टी को चेक द्वारा 5000/-रु० के हर्जाने का भुगतान कर दिया गया है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति में क्रम सं० 2 और 3 के मामलों में कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती । क्रम सं० 1 के मामले में अभी जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई है और मामले की जांच की जा रही है ।

Transfer of Telephones among Blood Relations

1948. SHRI K. M. KHAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether some instructions of M. T. N. L. exist for transfer of telephone connections among blood relations ;

(b) if so, the details of formalities to be undertaken by the transferer and charges to be paid by transferee ;

(c) whether some existing instructions in MTNL provide transfer of telephone connections in favour of persons having no blood relations ; and

(d) if so, the details of formalities to be undertaken by the transferer and charges to be paid by the transferee ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM) : (a) Sir, Instructions for transfer of telephones are issued by Department of Telecom which are followed in all the circles/Districts/MTNL. There is a provision for transfer of telephone among blood relations subject to fulfilment of certain conditions under transfer rules.

(b) All transfers will be carried out after receipt of application duly signed by both transferer and the transferee except in the case of the death of the hirer when it will be signed by the transferee only. The application should be accompanied with certificates indemnifying the Telecom Department against future claims and agreeing to pay all the previous dues etc.

In all bonafide cases of transferer, an amount of Rs. 100 per connection will be charged.

(c) There is a provision for transfer of a telephone in favour of a person who is not a blood relative which is covered under third party transfer rules.

(d) All transfers will be carried out after receipt of applications only signed by both transferer and transferee. The Application should be accompanied by a certificate indemnifying the Department of Telecom, against any future claims and agreeing to pay all previous dues, if any, etc.

In case of telephones sanctioned under N-OYT (General/Special) category the advance deposit will be refunded to the transferer after deduction of outstanding dues. The transferee will make the payment of advance rental and bi-monthly rental as applicable to telephones provided under N-OYT General category.

In case of telephones sanctioned under OYT scheme the balance of advance deposit will be refunded to the transferer after deduction of out-standing dues. The transferee will make payment of proportionate advance deposit for the remaining period under the scheme.

In addition to above a non-refundable transfer fee of Rs. 500/- will be collected from the transferee.

अल्मोड़ा के बासोट डाकघर की जमा योजनाओं की समीक्षा

1949. **श्री राजनाथ सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाकघरों की जमा योजनाओं की समय-समय पर कोई समीक्षा की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अल्मोड़ा जिले के बासोट डाकघर की जमा योजनाओं की कभी समीक्षा की गई है ;

(ग) यदि हां, तो कब तथा उसमें क्या खामियां पायी गयीं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त डाकघर में "किसान विकास पत्र", "इन्दिरा विकास पत्र" एवं "प्रधान मंत्री ग्रामीण महिला जमा योजना" जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ;

(ङ) यदि हां, तो विभाग द्वारा संबंधित डाकखाने के डाकपाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) इस डाकघर में उपरोक्त जमा योजनाओं की सुविधा कब से शुरु कर दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :

(क) से (ग) डाक विभाग डाकघर बचत बैंक का कार्य वित्त मंत्रालय के एक एजेंसी कार्य के बतौर निष्पादित करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर-वार बचत योजनाओं की कोई पुनरीक्षा नहीं करता है ।

(घ) बासोट डाकघर में महिला समृद्धि योजना और इन्दिरा विकास पत्र योजना उपलब्ध हैं, किन्तु यह डाकघर किसान विकास पत्रों की बिक्री के लिए प्राधिकृत नहीं है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) जब कभी औचित्य पाया जाएगा, इस डाकघर को किसान विकास पत्रों की बिक्री के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।